Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

मई (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की दिशा में की कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ 3
- हरियाणा सरकार शुरू करेगी 10 सेवा योजनाओं का सोशल ऑडिट 4
- हरियाणा के गृह मंत्री ने गीता सद्भावना यात्रा में भाग लिया 4
- हरियाणा में वन्य एवं घरेलू हितधारकों के संरक्षण हेतु कार्य-योजना तैयार 5
- गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव 5
- प्रदेश में हुई ई-फर्द प्रणाली लागू 6
- 'मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना'का स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये हुआ चयन 7
- 'हरियाणा ई-समीक्षा पोर्टल'पर होगी एक नई सुविधा की शुरुआत 7
- 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना'का हुआ शुभारंभ 8
- मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मिली स्वीकृति 9
- हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट लॉन्च की 10
- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को मिली स्वीकृति 11
- कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 में संशोधन को मिली स्वीकृति 11
- हरियाणा में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक विभाग का होगा गठन 12
- मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति- 2023-24 को दी मंजूरी 12
- मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रीवेंसिंज रिडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का किया लोकार्पण 14
- हाई पावर परचेज कमेटी व हाई पावर वर्क्स कमेटी की बैठक में 275 करोड़ रुपए की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी 15
- डबवाली बनेगा हरियाणा का अब नया पुलिस ज़िला 15
- राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन 16
- दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर और दिल्ली से पानीपत तक रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी 17
- बौनों और किन्नरों को हरियाणा सरकार का तोहफा 18
- रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच समझौते का हुआ आदान-प्रदान 18
- हरियाणा वन विभाग लगाएगा 3 लाख 78 हज़ार 250 पौधे 19
- आयुष मंत्री ने लॉन्च किया 'योग मानस' ऐप 19
- प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में हरियाणा पुलिस शीर्ष पर 20
- राज्य सरकार ने कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये उठाया अहम कदम 22
- हरियाणा खेती मासिक पत्रिका 'श्रीअन्न'विशेषांक का विमोचन 22
- मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का किया शुभारंभ 23
- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएँ होंगी पुरस्कृत 24
- मुख्यमंत्री ने की प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक 25
- भाला फेंक में नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बने 26
- हरियाणा स्टेट कैम्पा के तहत 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना को दी गई स्वीकृति 27
- मुख्यमंत्री ने निजामपुर सहित 9 गाँवों में पानी की समस्या दूर करने के लिये 34 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी 28
- विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई 'विदेश संपर्क कार्यक्रम' की मेजबानी 28
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 113 हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी 29
- सलेमपुर में 5 करोड़ की लागत से वीटा चिलिंग प्लांट प्रथम फेज का शिलान्यास 30
- हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ 31

नोट :

हरियाणा

मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की दिशा में की कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी के दूसरे दिन समापन सत्र अवसर पर जल संरक्षण की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

- जल संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ-
  - धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ किया जाएगा। इससे 218 एम.सी.एम. पानी की बचत होगी। इसके लिये मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा।
  - इसके अलावा, अगले दो वर्षों में 9500 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें 5308 तालाब, 63 चौक डैम, 81 उथले ट्यूबवैल और 4000 रिचार्ज बोरवेल शामिल हैं।
  - प्राकृतिक खेती के तहत 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करके इसके अधीन 6,000 एकड़ क्षेत्र से 25 हजार एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस प्रयास से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
  - राज्य सरकार ने खारे पानी वाले क्षेत्रों में 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसकी प्राप्ति के लिये कार्य में तेजी लाने के लिये कृषि विभाग केंद्रीय लवणीय मृदा सुधार संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा और अगले तीन महीनों में अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। इस कार्य के लिये मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि सब्सिडी का प्रावधान करना होगा तो वह भी किया जाएगा।
  - विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना का राज्य के 14 ज़िलों में विस्तार करने के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
  - पहले चरण में पंचवर्षीय योजना के तहत 700 करोड़ का बजट मिला था। दूसरे चरण में भी विश्व बैंक की ओर से लगभग 700 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे राज्य का जल भराव का 90 प्रतिशत क्षेत्र कवर हो जाएगा।
  - अगले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में पानी की 50 प्रतिशत मांग को एस.टी.पी. के ट्रीटेड वेस्ट वाटर द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि की जरूरतों के लिये 75 एस.टी.पी. के पानी का उपयोग किया जाएगा।
  - इतना ही नहीं, अगले दो वर्षों में 31 एचएसआईआईडीसी संपदाओं में से 18 में उपचारित अपशिष्ट जल का शत-प्रतिशत पुन: उपयोग किया जाएगा। एसटीपी का 50 फीसदी ही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको 100 फीसदी तक किया जाएगा।
  - पानी का उद्योग क्षेत्र में अधिक उपयोग करने के लिये राज्य सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत आईएमटी सोहना, आईएमटी खरखौदा और ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेड.एल.डी.) लागू करेंगे।
  - मत्स्यपालन के तहत क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में 2500 एकड़ में मत्स्यपालन किया जा रहा है, जिसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
  - ऊर्जा विभाग अगले 3 महीनों में यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुन: उपयोग करने के लिये परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करेगा।
  - आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिये ट्रीटेड वेस्ट वाटर के उपयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।

नोट :

- अगले दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 250 से अधिक शहरी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी लाइसेंसशुदा कॉलोनियों/एचएसवीपी सेक्टरों में माइक्रो एसटीपी और दोहरी पाइपलाइनों की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग सभी शहरी क्षेत्रों के पार्कों और हरित क्षेत्रों में किया जाएगा।

- उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अमृत जल क्रांति के अंतर्गत पंचकूला में आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया था।

हरियाणा सरकार शुरू करेगी 10 सेवा योजनाओं का सोशल ऑडिट

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में हरियाणा सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की 10 सेवा योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग शुरू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजनाएँ भी चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालित की जाएंगी।
- निदेशक सोशल ऑडिट यूनिट पीएमएवाई-जी, 15वें एफसीजीएस, एसबीएम, एनएसएपी, रूर्बन मिशन, सीनियर सिटीजन होम्स, नशा मुक्ति केंद्रों, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, पीएम-अजय, बाबू जगजीवन राम छत्रावास, आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति ऋण योजना और अत्याचार से संबंधित मामलों जैसी विभिन्न विकास योजनाओं के सामाजिक ऑडिट के संचालन के लिये एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा।
- बैठक में सोशल ऑडिट इकाई को सुदृढ़ करने के लिये ज़िला स्तर पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व एसडीओ पंचायती राज भी सदस्य होंगे। सोशल ऑडिट करने के लिये समिति विलेज रिसोर्स पर्सन की पहचान करेगी।
- गवर्निंग बॉडी ने विलेज रिसोर्स पर्सन के मानदेय को प्रति कार्य दिवस टीए, डीए सहित 500 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपए करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
- ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कहा कि सोशल ऑडिट यूनिट ने हरियाणा के सभी 22 ज़िलों से 824 ग्राम संसाधन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इनमें स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समूहों के सदस्य शामिल हैं।

हरियाणा के गृह मंत्री ने गीता सद्भावना यात्रा में भाग लिया

चर्चा में क्यों ?

30 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई गीता सद्भावना यात्रा में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- गीता सद्भावना यात्रा में पानीपत से विधायक महीपाल ढांडा सहित स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी हिस्सा लिया।
- सदभावना यात्रा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर से शुरू हुई और पारामाटा नदी के किनारे पर जाकर समाप्त हुई।
- उल्लेखनीय है कि गीता सद्भावना यात्रा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, स्वैच्छिक संगठनों ने भाग लिया।

नोट :

- गीता सद्भावना यात्रा के आयोजन का उद्देश्य गीता की सद्भावना के मूल संदेश को विश्व स्तर पर जनता के बीच फैलाना है।
- गीता हमेशा यह संदेश देती है कि पूरी मानवता एक है और इसे जाति, रंग और पंथ के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है।

हरियाणा में वन्य एवं घरेलू हितधारकों के संरक्षण हेतु कार्य-योजना तैयार

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2023 को हरियाणा राज्य जैव-विविधता बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा ने कम हो रही जैव-विविधता को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में वन्य एवं घरेलू हितधारकों को संरक्षण देने के लिये राज्य स्तर पर 2030 तक की कार्य-योजना तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इस कार्य-योजना को तैयार किया गया है, इसके तहत हरियाणा जैव-विविधता ज्ञान केंद्र भी बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र नवाचारों और तकनीकी के स्रोत के साथ-साथ एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करेगा।
- मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्य-योजना को स्वीकार करने से पहले और समय-समय पर निगरानी के लिये एक सब-कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में वित्त विभाग के अलावा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जो जैव-विविधता पर आँकड़े एकत्र करेगी और उसका बारीकी से अध्ययन करेगी।
- कलेसर पार्क में गत दिनों टाइगर देखा गया है। इसलिये वहाँ टाइगर पार्क बनाने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा। कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर एक माह में प्रस्तुत करेगी।
- कार्य-योजना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा गाय, भैंस, बंदर, नीलगाय आदि प्रजातियों को बचाने के लिये कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, खेती योग्य भूमि, भूमिगत जल, शहरी क्षेत्र में हाई राइज मंजिलों में रहने वाली आबादी के लिये पर्याप्त मात्रा में पेयजल आदि के प्रबंधन को लेकर भी कार्य किया जाएगा।

गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव

चर्चा में क्यों ?

4 मई,2023को हरियाणा के करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव मनाया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनेक घोषणाएँ कीं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक पीठ (चेयर) स्थापित की जाएगी, जो उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर शोध करेगी।
- मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी-पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में बीसी (ए) वर्ग को आरक्षण प्रदान किया था। अब नगर निकायों में भी इसी तर्ज पर बीसी (ए) वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- बच्चों को बाबा गोरखनाथ की शिक्षाओं से अवगत करवाने के लिये गुरु गोरखनाथ की जीवनी व उनकी शिक्षाओं का उल्लेख स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा।
- योगी समाज जहाँ सहमति प्रदान करेगा, उन शहरों में गुरु गोरखनाथ के नाम पर चौक या मार्गों का नाम रखा जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार ने संत-महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु संत-महापुरुष सम्मान एवं प्रचार-प्रसार योजना के तहत सभी संत-महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। यह स्मृति उत्सव भी इसी कड़ी में आयोजित किया गया है।

प्रदेश में हुई ई-फर्द प्रणाली लागू

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2023 को ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिये प्रदेश में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई-फर्द प्रणाली की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- ई-फर्द प्रणाली लागू होने से अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिये पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि www.jamabandi.nic.in पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द अर्थात् नकल प्राप्त कर सकेंगे।
- विदित है कि पहले फर्द प्राप्त करने के लिये पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, यहाँ तक कि इसमें महीनों का समय लगता था लेकिन अब यह काम घर बैठे मिनटों में ही हो जाता है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर, 2022 को www.jamabandi.nic.in पोर्टल शुरू किया था। एक फर्द के लिये सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपए है और पहले खेवट के लिये 10 रुपए तथा इसके बाद के प्रत्येक खेवट के लिये 5 रुपए फीस देनी होती है।
- जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड संबंधी जानकारी के लिये सिंगल विंडो का काम करता है। इस पोर्टल पर ही ई-फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा, खतौनी ज़मीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- प्रदेश की सभी 143 तहसीलों/उप तहसीलों में वैब- हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया है तथा सभी राजस्व रिकॉर्ड रूम का भी कंप्यूटरीकरण कर दिया है।
- प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों तथा राज्य मुख्यालय पर डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किये गए थे। इस नई पहल के तहत महत्त्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेज़ों को स्कैन व सूचीबद्ध करके आधुनिक रिकॉर्ड रूम में डिजिटल बॉक्स में रखा गया है। इसके लिये 18 करोड़ 50 लाख दस्तावेज़ों को स्कैन किया गया है। आई.टी. की सहायता से अब रिकॉर्ड को मेंटेन करना और ज़रूरत पड़ने पर इसे ढूंढ़ना आसान हो गया है।

'मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना'का स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये हुआ चयन

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2023 को हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि राज्य में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण व स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना'को स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कोरोना काल में 5 अगस्त, 2020 को 'मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना'शुरू की गई थी।
- 'मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना'के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर चिह्नित बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं में विटामिन ए व डी 3 की कमी को दूर करने के मकसद से स्किम्ड दूध को साल में 300 दिन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था।
- विभाग के मुख्यालय व ज़िला स्तर के अधिकारियों की निगरानी व आंगनवाडी केंद्र पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिकाओं के सहयोग से निरंतर लाभार्थियों के स्वास्थ्य, विशेषकर उनकी पोषण स्थिति में सकारात्मक सुधार देखने को मिला।
- प्रदेश में 6 माह से 6 साल तक के 9 लाख 23 हज़ार बच्चों, 2 लाख 88 हज़ार गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में छह दिन गुलाब, इलायची, चॉकलेट, वनीला, बटरस्काच व सादा दूध स्वाद में दूध उपलब्ध करवाया गया है।
- इस दूध के माध्यम से लाभार्थियों को प्रोटीन, कैलोरी, कैल्सियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी12, विटामिन ए व डी3 की प्रचुर मात्रा मिली है, जिसके कारण प्रदेश में पोषण के नजरिये से सामान्य श्रेणी के बच्चों की संख्या में 3.67 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, जबकि मध्यम रूप से कम वज़न वाले बच्चों में 3.66 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है।
- विदित है कि स्कॉच संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक-प्रशासनिक दृष्टि से नवोन्मेषी प्रयासों के माध्यम से बदलाव लाने के प्रयासों को प्रोत्साहन देता है और पूर्व में भी हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों को नवोन्मेषी प्रयासों के लिये सम्मानित किया गया था।

'हरियाणा ई-समीक्षा पोर्टल'पर होगी एक नई सुविधा की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मानव संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार 'हरियाणा-ई-समीक्षा पोर्टल'पर एक नई सुविधा शुरू करेगी ताकि प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष अपनी बैठकों और प्रस्तुतियों के दौरान लिये गए निर्णयों पर की गई 'फॉलोअप एक्शंस'की निगरानी कर सकें।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 'हरियाणा ई-समीक्षा पोर्टल'एक रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम है जिसे प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान किये गए निर्णयों पर की गई 'फॉलोअप एक्शंस'की निगरानी के लिये डिज़ाइन किया गया है। यदि आवश्यक हो तो सिस्टम को अन्य मीटिंग्स से 'फॉलोअप एक्शन्स'की समीक्षा करने के लिये भी कॉन्फिगर किया जा सकता है।
- कॉन्फिगर की यह नई सुविधा बैठकों और प्रस्तुतियों के दौरान किये गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों की निगरानी और ट्रैकिंग को बढ़ाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- यह पोर्टल फाइल नंबर, बैठक की तारीख, बैठक के अध्यक्ष, बैठक विवरण और बैठक के मिनट्स (एमओएम) जैसे अन्य दस्तावेज़ों पर अपडेट प्रदान करेगा, जिसे संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त यह पोर्टल ऑनलाइन जमा करने से लेकर अनुपालन तक कार्य बिंदुओं, प्रस्तावों, मुद्दों, परियोजनाओं, योजनाओं और लक्ष्यों की स्वचालित ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना'का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के पंचकूला ज़िले से 'मुख्यमंत्री तीर्थ योजना'की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा तथा इसके बाद 60 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, जो तीर्थयात्रा पर जाना चाहगे उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
- गौरतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में तीर्थयात्रा करने का सपना होता है, इसलिये सरकार ने यह योजना बनाई है। इस योजना के तहत सबसे पहले अयोध्या यात्रा की योजना बनाई है, जिसमें लगभग 200 वृद्ध जन 5 मई से 8 मई तक श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा करेंगे। इन यात्रियों का आने-जाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

नोट :

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

8 मई,2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिये गहन जाँच की।
- इस रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए (बीसी-ए) के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद नागरिकों के ब्लॉक-ए के पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित होगा और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो सकती है।
- शहरी स्थानीय क्षेत्र, उस शहरी स्थानीय क्षेत्र में कुल आबादी के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी । यदि दशमलव मान 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का दो प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक निकाय में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा।
- नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में महापौरों/अध्यक्षों के पदों की संख्या का आठ प्रतिशत नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के लिये आरक्षित होगा।
- आयोग ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण किसी भी नगर निकायों में अनुसूचित जाति और बीसी (ए) के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- पिछड़े वर्ग (ए)के लिये इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या के साथ जोड़ने पर यदि उनकी कुल संख्या नगर निकायों की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो पिछड़े वर्ग (ए) के लिये आरक्षित सीटों की संख्या को वहीं तक रखा जाएगा जिससे कि अनुसूचित जाति और बीसी (ए) का आरक्षण नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के सदस्य की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। उदाहरण के लिये शहरी स्थानीय क्षेत्र में, 'ए'नागरिकों के ब्लॉक ए के पिछड़े वर्ग की आबादी उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी का 25 प्रतिशत है, तो 12.5 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग के ब्लॉक-ए नागरिकों के लिये आरक्षित होंगी।

नोट :

- जहाँ किसी दिये गए शहरी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहाँ के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए को उनकी आबादी के प्रतिशत के बावजूद कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।
- जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या का 40 प्रतिशत है तथा शहरी स्थानीय क्षेत्र में 10 सीटें हैं तो अनुसूचित जाति के लिये 4 सीटें आरक्षित होंगी, शेष एक सीट पिछड़ा वर्ग ब्लॉक के लिये उपलब्ध होगी।
- पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए के नागरिकों को नगर पालिका में एक सीट मिलेगी, भले ही उनके लिये उपलब्ध आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार कोई सीट उपलब्ध न हो, बशर्ते कि संबंधित शहरी स्थानीय क्षेत्र में उनकी आबादी 2 प्रतिशत से कम न हो।

हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट लॉन्च की

चर्चा में क्यों ?

8 मई, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट लॉन्च की।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की वेबसाइट बनने से प्रदेश में सिविल एविएशन विभाग को एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लागू करने और तेजी से पूरा करने में आसानी होगी। इससे हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के साथ-साथ अन्य सभी हवाई पट्टियों के विकास कार्यों की निगरानी और निरीक्षण के कार्य शीघ्रता से पूरे होंगे।
- इस वेबसाइट के शुरू होने से हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में सिविल एविएशन विभाग में किये जा रहे विकास कार्यों को दुनिया में कहीं से कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
- इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य में हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के गठन को सिविल एविएशन के क्षेत्र में अहम् बताते हुए कहा कि इसके गठन से हवाई अड्डों के संचालन के लिये उपकरणों और वस्तुओं की खरीद करने में आसानी होगी और काम में तेजी आएगी। जब भी आवश्यकता होगी तो हवाई अड्डों के विकास के लिये तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट की समीक्षा की जा सकेगी।
- यही नहीं, अब विमानन गतिविधियों के लिये निविदा दस्तावेज़ों की तैयारी और प्रकाशन आसान होगा, उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण हो सकेगा।
- हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के गठन से हवाई अडन्नें के बुनियादी ढाँचे की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन में सहायता मिलेगी और राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की संस्थागत क्षमता निर्माण भी होगा।

नोट :

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में संशोधन के अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- इन अध्यादेशों को हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जाएगा।
- संशोधन के अनुसार, प्रत्येक नगर पालिका में पिछड़े वर्ग 'ए'के लिये सीटें आरक्षित होंगी और आरक्षित सीटों की संख्या यथासंभव रहेगी।
- नगर पालिका में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में उस नगर पालिका की कुल आबादी के लिये पिछड़े वर्ग 'ए'जनसंख्या के अनुपात का 0.5 या अधिक होने की स्थिति में अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाता है।
- अनुसूचित जाति के लिये पहले से ही आरक्षित सीटों को छोड़कर पिछड़े वर्ग 'ए'की सबसे अधिक प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े वर्ग 'ए'के आरक्षण के लिये प्रस्तावित सीटों की संख्या के अधिकतम तीन गुना सीटों में से ऐसी सीटों को ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में भी बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी।
- मंत्रिपरिषद ने 8 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग-ए को नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने में आरक्षण के अनुपात के प्रावधान के लिये हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
- चूँकि, राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द से जल्द होने हैं इसलिये हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों और नगर परिषदों/समितियों के चुनावों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण के प्रावधान के लिये, अधिनियम, 1994 की धारा 6 और धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में प्रावधान करने के लिये अध्यादेश लाने की आवश्यकता है।

कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 में संशोधन को मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 'बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम'के अंतर्गत 25 परियोजनाएँ और 'इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन स्कीम'के तहत 15 अतिरिक्त परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।
- नीतिगत बजट 433 करोड़ रुपए का अपरिवर्तित बजट रहेगा। व्यक्तिगत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण, विस्तार और विविधीकरण की योजना से 31 मार्च, 2024 तक या नई कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, 160 करोड़ रुपए का बजट उपरोक्त योजनाओं में परिवर्तित किया जाएगा।
- यह संशोधन वांछित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार होगा और एक वृहद खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के साथ-साथ राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिये भी उपयोगी होगा।
- हरियाणा कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति को कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास प्राप्त करके एक समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने, मजबूत मूल्य श्रृंखला लिंकेज बनाने, अनुसंधान पर ज़ोर देने और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे की स्थापना के दृष्टिकोण के साथ अधिसूचित किया गया था।
- इस नीति का उद्देश्य हरियाणा को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों के लिये एक स्पष्ट गंतव्य बनाना, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, पशुधन, मत्स्य और पोल्ट्री आदि में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और निवेश करके बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना था।

नोट :

- साथ ही खाद्य प्रसंस्करण समूहों में, इस प्रकार एक मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित करना, ताजा भोजन विशेष रूप से फल, सब्जियाँ, दूध और मछली के फार्म द्वार प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, कृषि-व्यवसाय स्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और किसानों को नए माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाने और कृषि-विपणन सुधार करना है।
- इस नीति को अधिसूचित करने का उद्देश्य वर्ष 2023 तक 3,500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 20,000 लोगों के लिये रोज़गार सृजन करना और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं (फल, सब्जियाँ), डेयरी, मत्स्य पालन आदि में प्रसंस्करण के स्तर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना था।

हरियाणा में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक विभाग का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

- 9 मई, 2023 को हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक एक नया विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय सभी लेखा परीक्षा योग्य इकाई सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों, +स्थानीय प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित या वित्तपोषित अन्य प्राधिकरणों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा।
- इनमें समेकित निधि से धन, सहायता, अनुदान या योगदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन और संस्थाएँ जो राज्य संचित निधि के माध्यम से सरकार से किसी भी रूप में या सार्वजनिक रूप से धन प्राप्त करती हैं, वे भी इस लेखा परीक्षा में शामिल हैं।
- आंतरिक नियंत्रण के लिये आंतरिक लेखा परीक्षा की समीक्षा और सुधार करने, कमजोरियों एवं गलतियों की पहचान करने, मूल्यांकन और निगरानी के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण के लिये जाँच का पर्याप्त और प्रभावशाली उपकरण है।

मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति- 2023-24 को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

- 9 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति- 2023-24 को अनुमोदित किया गया है।

नोट :

- गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में जिस लाइसेंस फीस पर फुटकर दुकानें आवंटित की गई थीं, उसकी शत-प्रतिशत वसूली राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है।
- नई आबकारी नीति- 2023-24 उन संसाधनों को उत्पन्न करने की सुविधा भी देती है, जिनका उपयोग विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये किया जा सकता है।
- पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करना है।
- इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए के लक्षित संग्रह के साथ खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है। इस राशि का उपयोग पर्यावरण और पशु कल्याण के लिये किया जाएगा।
- पर्यावरण रक्षा और पशु कल्याण (गौ सेवा) के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नई नीति में खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है, जिसका लक्ष्य 400 करोड़ रुपए संग्रह करना है। इस राशि का उपयोग पर्यावरण एवं पशु कल्याण के लिये किया जाएगा।
- नई नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिये ज़िला स्तर पर आईएफएल (बीआईओ) के लेबल का भी नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये छोटी (क्राफ्ट) ब्रेवरीज की लाइसेंस फीस कम की गई है। राज्य में वाइनरी को बढ़ावा देने के लिये वाइनरी की सुपरवाइजरी फीस में कमी की गई है।
- नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को क्रमश: 2022-23 में 2600 से घटाकर 2500 तथा 2023-24 में 2500 से 2400 कर दिया गया है।
- इसी के साथ लोक कल्याण की दृष्टि से एक और बड़ा फैसला लेते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आस-पास अधिसूचित पवित्र क्षेत्रों तथा जिन गाँवों में गुरुकुल चल रहे हैं, वहाँ शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे।
- वर्तमान नीति में, अधिक से अधिक प्रतिभागियों को ई-निविदा के माध्यम से शराब की दुकान के लाइसेंस के लिये आवेदन करने की अनुमति देने के लिये खुदरा शराब बिक्री ज़ोन का आकार भी चार से घटाकर दो कर दिया गया है।
- नई नीति में देशी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब और आयातित विदेशी शराब (बीआईओ) के मूल कोटे में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही देशी शराब और आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की दरों में भी मामूली वृद्धि की गई है।
- अल्कोहल की कम मात्रा वाले पेय पदार्थों को बढ़ावा देने के लिये रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेज और बीयर पर माइल्ड और सुपर माइल्ड कैटेगरी के तहत एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। इसके अलावा, पब कैटेगरी (एल-10ई) यानी केवल बीयर और वाइन के उपभोग के लिये लाइसेंस शुल्क को और कम कर दिया गया है।
- नई नीति में थोक लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की चोरी पर अंकुश लगाने के लिये जुर्माने के प्रावधान कड़े किये गए हैं और लाइसेंसधारक द्वारा सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शराब प्रचार के विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- आबकारी लाइसेंस के तहत शराब परोसने वाले सभी होटलों, पब और बार, रेस्तरां और कैफे के बाहर सावधानी बोर्ड प्रदर्शित किये जाएंगे। इसके अलावा, कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों के लिये सभी खुदरा विक्रेताओं के लिये अग्निशमन उपकरण स्थापित करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी दुकानों/गोदामों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।

नोट :

मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रीवेंसिंज रिडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम ग्रीवेंसिंज रिडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल पर जन संवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं एवं सुझावों को अपलोड कर पूरा लेखा-जोखा रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्त्ता के पास समस्या के बारे में संदेश भी जाएगा।
- विदित है कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 600 से अधिक सेवाएँ आती हैं।
- उल्लेखनीय है कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत 13 से 15 मई तक राज्य के सिरसा ज़िले में चतुर्थ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा सिरसा ज़िले के कई गाँवों के लोगों से सीधे रूबरू होकर संवाद किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ संवाद करते समय सरकार के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को कार्यान्वित करने के लिये ज़िला एवं मुख्यालय स्तर पर इन समस्याओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिये शहरी स्तर पर 'नगर दर्शन पोर्टल'एवं गाँव स्तर पर 'ग्राम दर्शन पोर्टल'बनाए गए हैं। इन पर नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याओं एवं विकास कार्य करवाने के लिये भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वह शिकायत अधिकारी के पास स्वत: ही चली जाएगी और वे उन पर संज्ञान लेकर एस्टीमेट एवं बजट आदि का प्रावधान कर पूरा करने का कार्य करेंगे।
- पहले इन पोर्टल पर आने वाली समस्याओं को प्रतिनिधियों के माध्यम से सहमति प्रदान की जाती थी, लेकिन अब नागरिक सीधे ही इन समस्याओं को पोर्टल पर भेज सकते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को अच्छी सेवाएँ प्रदान करने के लिये बेहतर मैकेनिज्म तैयार किये गए हैं जिस पर जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है। अब तक इस डेमो पोर्टल पर 3609 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की हैं।
- ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री हर शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसी एक वर्ग के साथ संवाद करते हैं। इनमें लोगों से सीधी बातचीत होती है और कार्यकर्त्ता भी इनसे जुड़ते हैं। इसके अलावा संबंधित अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, जो उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करते हैं।

नोट :

हाई पावर परचेज कमेटी व हाई पावर वर्क्स कमेटी की बैठक में 275 करोड़ रुपए की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 275 करोड़ रुपये की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में सिंचाई, पुलिस, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कुल 26 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 18 एजेंडे को मंजूरी दी गई।
- बैठक में पशु बीमा के लिये भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही 'पशु बीमा योजना' के तहत किसानों को 70 करोड़ रुपये का क्लेम दिया गया।
- राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने हेतु व्यस्थाओं को सुव्यवस्थित किया है। पहले केवल एल-1 पार्टी से ही नेगोशिएशन किया जाता था, अब यह सिस्टम बनाया गया है कि बोली राशि के 5 प्रतिशत तक की रेंज में एल-5 तक पार्टियों को नेगोशिएशन के लिये बुलाया जाता है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से रेट तय किये जा सकें।

डबवाली बनेगा हरियाणा का अब नया पुलिस ज़िला

चर्चा में क्यों ?

14 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे की बुरी आदत पर रोक तथा नशा तस्करों पर सख्ती के लिये आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में राज्य के सिरसा ज़िले का उपमंडल डबवाली का नया पुलिस ज़िला बनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि ज़िला पुलिस के प्रमुख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त पुलिस प्रशासन में कई पुलिस अधीक्षक (एसपी)/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडीएल एसपी) भी सम्मिलित होते हैं। ज़िले को कई पुलिस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसका नेतृत्व क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डबवाली की अनाज मंडी को विस्तार देने के लिये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 6.8 एकड़ भूमि भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देने के लिये स्वीकृति प्रदान की।

नोट :

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

12 मई, 2023 को हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को किसान हितैषी बनाने के लिये खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक लागू करने हेतु महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए, जिससे योजना को प्रदेश के लोगों के लिये अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया जा सके।

बैठक में तकनीकी के प्रयोग को महत्त्वता देते हुए तकनीकी समर्थन हेतु हरसैक को विभाग का तकनीकी भागीदार नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा आगामी सत्र के लिये जारी होने वाले टेंडर में किसानों की शिकायतें पोर्टल के माध्यम से लेने का प्रावधान किया जाएगा।

योजना की पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा फसल कटाई प्रयोगों की विडियोग्राफी तथा स्थानीय आपदा के सर्वे/फसल कटाई प्रयोगों में आपत्ति करने का समय 72 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तथा बीमा कंपनी के लिये 48 घंटे से बढ़ाकर 96 घंटे करने की सिफारिश की।

इस बैठक में योजना के तहत सम्मिलित फसलों की बीमित राशि भी तय की गई। जिसका विवरण प्रकार निम्न दिया गया है:&

राशि रुपए प्रति हैक्टेयर							
खरीफ				रबी			
फसल	2023-24	2024-25	2025-26	फसल	2023-24	2024-25	2025-26
धान	96371	101190	106249	गेंहूँ	72896	76541	80368
बाजरा	46456	48779	51218	सरसों	48927	51373	53942
मक्का	49421	51892	54487	जौं	46456	48779	51218
कपास	98595	103525	108701	चना	35830	37682	39503
मूंग	43243	45405	47675	सूरजमूखी	49421	51892	54487

नोट :

दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर और दिल्ली से पानीपत तक रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2023 को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली-गुरुग्राम-शाहजहाँपुर-नीमराणा-बहरोड़ (एसएनबी)-अलवर और दिल्ली से पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति ली जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में बताया गया कि दिल्ली-एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 107 किमी. होगी। इसमें 70 किमी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष किमी. अंडरग्राउंड होगा। इस पर 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और 1 एट-ग्रेड स्टेशन होंगे। धारूहेड़ा में एक डिपो बनाने की योजना है।
- दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुज़रने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई क्रमश: 23 किमी., 83 किमी. और 2 किमी. है।
- प्रस्तावित अलायनमेंट का एलिवेटेड हिस्सा पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम, गुरुग्राम में सेक्टर-17 के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और एसएनबी (राजस्थान सीमा) तक एनएच-40, 48 के बीच होगा।
- दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जबकि केंद्र सरकार की स्वीकृति विचाराधीन है। दिल्ली-एसएनबी कॉरिडोर के प्रस्तावित स्टेशनों में सराय काले खाँ, आईएनए, मुनीरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर-17, राजीव चौक, खेड़कीदौला, मानेसर, पंचगाँव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, एमबीआईआर, रेवाड़ी, बावल और एसएनबी हैं।
- 103 किमी. लंबे अलायनमेंट के दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर का 11.5 किमी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष 91.5 किमी. हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 अंडरग्राउंड, 14 एलिवेटेड और 2 एट ग्रेड स्टेशन होंगे। मुरथल और पानीपत में दो डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली में इसकी लंबाई 36.2 किमी. जबकि हरियाणा में 66.8 किमी. होगी।
- एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बताया कि दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का साहिबाबाद से दुहाई तक तक 17 किमी. लंबा हिस्सा चालू होने वाला है।
- उल्लेखनीय है कि एनसीआरटीसी भारत सरकार एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इसमें भागीदार राज्य हैं।

नोट :

बौनों और किन्नरों को हरियाणा सरकार का तोहफा

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के बाद अब बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता एक अप्रैल 2023 से लागू होगा।

प्रमुख बिंदु

- बौना भत्ता के लिये पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिये आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।
- इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपए मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक दी जाएगी।
- 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपए की गई है।
- इन दोनों योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिये व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिये और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है, परंतु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच समझौते का हुआ आदान-प्रदान

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में नगर निगम रोहतक की 15.37 एकड़ भूमि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से 33 वर्षों की लीज पर आवंटित करने हेतु नगर निगम रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच समझौता हुआ और दस्तावेज़ एक्सचेंज किये गए।

प्रमुख बिंदु

- गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा किया गया है, जिससे इस भूमि का उपयोग मौज़ूदा शैक्षणिक संस्थान के विस्तार के लिये किया जाएगा।
- सभा के पदेन सचिव डॉ. जयपाल शर्मा ने बताया कि सभा 100 से अधिक शिक्षण संस्थाएँ चला रही हैं और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा एक स्नातक महाविद्यालय, 1 बी.ए. महाविद्यालय तथा 1 विद्यालय चलाया जा रहा है। इन संस्थानों में लगभग 3700 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
- विदित है कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को वर्ष 2008 में पहरावर ज़मीन लीज़ पर दी गई थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम रोहतक बना और यह ज़मीन निगम के अधीन आ गई। लीज़ राशि का भी भुगतान नहीं हुआ। इस बीच हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ज़मीन का अधिग्रहण किया, विवाद बढ़ा और एचएसवीपी ने ज़मीन को रिलीज़ कर दिया।
- हाल ही में करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में इस ज़मीन को नए सिरे से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देने की घोषणा की गई थी। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंज़ूरी देकर अब स्वीकृति-पत्र एवं लीज़ दस्तावेज़ सभा को सौंपे गए हैं।
- सभा इस ज़मीन का उपयोग शिक्षण संस्थान बनाने के लिये करेगी। लीज़ में 5 साल का समय दिया गया है। यदि 5 साल में भी संस्थान का निर्माण नहीं हो पाता तो और 5 साल का समय दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान कई घोषणाएँ की गई जिसमें से अधिकांश पूरी हो गई हैं। इनमें भगवान परशुराम के नाम पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करना, कैथल में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर करना और परशुराम जयंती पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा करना शामिल है।
- इसके अलावा, पुजारी-पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना का काम पाइपलाइन में है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।

नोट :

हरियाणा वन विभाग लगाएगा 3 लाख 78 हज़ार 250 पौधे

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को हरियाणा वन विभाग के एक प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिये 90 किस्मों के 3 लाख 78 हज़ार 250 पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें मानसून की पहली बारिश के बाद लगाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- पौधारोपण में मुख्य रूप से औषधीय पौधे, फल देने वाले, छाया देने वाले व लकड़ी देने वाले पौधे लगाए जाएंगे।
- प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती ज़मीन, मुख्य मार्ग, स्कूल, कॉलेज, श्मशान घाट, खेल के मैदान, सरकारी शिक्षण संस्थान आदि में मानसून आने के बाद पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण में पौधागिरि के तहत 75 हज़ार, जल शक्ति के तहत 1 लाख व 75 हज़ार पौधे नि:शुल्क दिये जाएंगे।
- इस कार्य में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, विद्यालयों का भी सहयोग लिया जाएगा।
- विदित है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिये पौधारोपण ज़रूरी है। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं, जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं व मिट्टी को संरक्षित करने के अलावा पर्यावरण को कई अन्य तरीकों से भी लाभान्वित करते हैं।
- पौधे जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये फल, लकड़ी, फाइबर, रबर आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ हवा से कणों को फिल्टर भी करते हैं, इस प्रकार इसे स्वच्छ और जहरीले पदार्थों से मुक्त बनाते हैं।

आयुष मंत्री ने लॉन्च किया 'योग मानस' ऐप

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने आयुष विभाग के 'योग मानस' (योगशाला मैनेजमेंट एंड ऐनालिटीकल सिस्टम) ऐप की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर आयुष मंत्री ने बताया कि बेहतर जीवन जीने, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा अदभुत मनुष्य तैयार करने हेतु योग विद्या को बढ़ावा देने के लिये इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों की योग गतिविधियों, योग सहायकों द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही इत्यादि पर निगरानी भी रखी जा सकेगी।

नोट :

- इस ऐप के माध्यम से योग में भाग लेने के लिये नागरिक/प्रतिभागी अपने मोबाइल से पंजीकरण कर सकता है। ऐप में ज़िला आयुष अधिकारी का लॉगइन दिया गया है तथा योग सहायक के मॉड्यूल के साथ-साथ डैशबोर्ड दिया गया है, जिसके माध्यम से योग की गतिविधियों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा नज़र रखी जा सकेगी।
- नागरिक/प्रतिभागी को अपने मोबाइल में योग मानस एप्लीकेशन को इंस्टाल करना होगा और उसके बाद नागरिक/प्रतिभागी को अपनी बेसिक जानकारी डालकर इसे चालू करना होगा।
- ऐप के चालू होने के बाद जीपीएस के माध्यम से नागरिक/प्रतिभागी के आस-पास की योगशालाओं का लोकेशन दिखाई देगा। नागरिक/प्रतिभागी अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित योगशाला में अपना पंजीकरण करने पर अपने सत्र को सब्सक्राइब करेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात् नागरिक/प्रतिभागी का एनरोलमेंट हो जाएगा।
- आयुष मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार से योग सहायकों की अलग से लॉगइन प्रक्रिया है। योग सहायक को अपनी जीपीएस लोकेशन ऑन करना होगा और अपनी योगशाला का चयन करना होगा। उसके पश्चात् उसे अपने सत्र/बैच का सृजन करना होगा तथा उसके बाद सत्र/बैच की जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद वह अपनी हाजिरी को मार्क भी कर पाएगा।
- इस एप्लीकेशन में विभिन्न प्रकार के योग के आसनों की सूची भी दी गई हैं, जिसे नागरिक/प्रतिभागी अपने अनुसार कस्टमाइज कर पाएगा। एप्लीकेशन में ज़िला आयुष अधिकारी का लॉगइन दिये जाने से वह योगशाला, योग सहायक, योग सत्रों सहित सब्सक्रिप्शन की निगरानी कर सकेगा।

प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में हरियाणा पुलिस शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई स्टेट अपेक्स कमेटी फॉर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) की बैठक में बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिये किये जाने वाले मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग शीर्ष पर है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सीसीटीएनएस हरियाणा परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक-मित्रता को बढ़ाना, पुलिस संचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करना है।
- हाल ही में, हरियाणा के पुलिस विभाग ने एक नई सुविधा भी शुरू की है, जिसमें शिकायतकर्त्ताओं को हिन्दी में एसएमएस के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) स्टेटस अपडेट भेजे जाते हैं। संदेशों में एफआईआर डाउनलोड करने के लिये एक लिंक भी शामिल है।
- हरियाणा के कुल 277 पुलिस स्टेशनों में बैंडविड्थ को अपग्रेड किया गया है, जो हरियाणा पुलिस की लगातार कनेक्टिविटी में सुधार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अधिकारियों से स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया, इससे राज्य भर में साइबर अपराध रोकथाम और सहायता योजना सहित नव स्थापित 47 पुलिस स्टेशनों को 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ मिलेगी।
- बैठक में बताया गया कि राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सीसीटीएनएस प्रणाली में विभिन्न रिपोर्ट विकसित की गई हैं।
- इसके अलावा, विशेष रूप से रक्का (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सिस्टम में डॉक्टर द्वारा उत्पन्न एक दस्तावेज़) को संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को सीसीटीएनएस के माध्यम से भेजने के लिये एक नया प्रावधान किया गया है। एसएचओ और संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजा जाता है।
- साथ ही, मेडलीएपीआर में संग्रहीत मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) के लिये इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है।
- बैठक में जानकारी दी गई कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) को सीसीटीएनएस के साथ जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस एकीकरण से नागरिक ऑनलाइन उपकरणों को ब्लॉक करने या अनब्लॉक करने के लिये अनुरोध करने हेतु सक्षम हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त, सीसीटीएनएस के साथ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के माध्यम से अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य, जेल, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), अभियोजन और न्यायालयों के साथ सफल एकीकरण किया गया है।
- यह उपलब्धि इन विभागों के बीच निर्बाध सूचना साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली को और मज़बूत किया जा सकता है।

नोट :

राज्य सरकार ने कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये उठाया अहम कदम

चर्चा में क्यों ?

21 मई, 2023 को हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रदेश सरकार की योजना के तहत राज्य की कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये अहम कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पाँच हज़ार रुपए मिलेंगे।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिये 'मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना'शुरू की है।
- इस योजना के तहत गत वर्ष आठ मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिये गए हैं।
- अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएँ भी इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होंगी।
- योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस योजना के लिये आधार कार्ड अनिवार्य है।
- केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिये गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जाँच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है।
- 'मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना'का लाभ लेने के लिये आंगनवाड़ी वर्कर या आशा के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिये पहले से 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना'संचालित की जा रही है, जिसके तहत पाँच हज़ार रुपए की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किस्तों में देने का निर्णय लिया गया है।

हरियाणा खेती मासिक पत्रिका 'श्रीअन्न'विशेषांक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

21 मई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष 2023 मनाने की कड़ी में हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने हरियाणा खेती मासिक हिन्दी पत्रिका के 'श्रीअन्न'विशेषांक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- कुलपति ने बताया कि इस विशेषांक में पोषक अनाज वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, सांवक, छोटी कंगनी व कुटकी आदि के उत्पादन, महत्त्व, रख-रखाव, मूल्य-संवर्धन, खाद्य पदार्थ बनाने, स्वादिष्ट व्यंजन बनाने तथा स्वास्थ्य से संबंधित विशेष जानकारियाँ विशेषज्ञों द्वारा दिये गए लेखों के रूप में दी गई हैं, जिसका उद्देश्य सभी पाठकों को पोषक अनाजों व इनसे होने वाले फायदे से अवगत करवाना है।
- विदित है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण को बढ़ावा देने के लिये भारत के आह्वान् पर देश अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का नेतृत्व कर रहा है। भारत 8 करोड़ टन से अधिक उत्पादन के साथ मोटे अनाजों के लिये वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।
- रागी (फिंगर मिलेट) कैल्शियम व पोटेशियम का सबसे बेहतरीन स्रोत है, वहीं चेन्ना (प्रोसो मिलेट) और कुटकी (लिटिल मिलेट) विटामिन बी-6, फास्फोरस, फाइबर तथा एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं।
- कंगनी (फॉक्सटेल मिलेट) प्राचीन फसलों में से एक है तथा इसमें बीटा केरोटिन, विटामिन और खनिज तत्त्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह विशेष तौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिये लाभप्रद है।

नोट :

- कोडो मिलेट औषधीय गुणों से भरपूर है और यह कफ और पित्त दोष को शांत करता है तथा इसमें बैक्टीरिया व जलन रोधी गुण होने के कारण लाभप्रद है। इसको खून शोधक व तंत्रिका तंत्र को मजबूत रखने हेतु भी प्रयोग में लिया जाता है।
- इनके अतिरिक्त सावंक व छोटी कंगनी भी पौष्टिक होने के साथ औषधीय गुणों से भरपूर हैं।

मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन कल्याण की दिशा में एक और अभिनव पहल करते हुए राज्य के गुरुग्राम ज़िले से कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को 1 जून, 2023 से पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मज़बूत करने और ज़िला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है।
- मुख्यमंत्री ने हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर भी जारी किया और कहा कि इस आउटरीच कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं, जो अपने निवासियों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा।
- अपने ज़िले के जनप्रतिनिधियों के रूप में सभी को एक सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में मिलकर काम करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ज़िला उपायुक्त, पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- हरियाणा उदय के तहत चीफ मिनिस्टर आउटरीच कार्यक्रम के कैलेंडर में जून माह के दौरान स्ट्रांग/फिटमैन हरियाणा, गुरुग्राम में 3 दिवसीय महिला बाज़ार तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- इसके अलावा, जुलाई माह के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिये खेल प्रतियोगिताओं तथा फरीदाबाद में 3 दिवसीय महिला बाज़ार का आयोजन किया जाएगा।
- कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ज़िला उपायुक्त 1 जून, 2023 से अपने संबंधित ज़िलों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- इन कार्यक्रमों में गाँव जनसंवाद/क्षेत्र जन संवाद, जन भागीदारी के साथ तालाब की सफाई, स्कूलों/मोहल्लों के स्पोर्ट्स लीग में संगीत, कला और कविता प्रतियोगिताएँ, पौधारोपण अभियान, ज़िले के आईएएस व एचसीएस अधिकारियों द्वारा सप्ताह में एक बार गाँवों में रात्रि प्रवास कार्यक्रम, युवा संसद/गाँव संसद, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई व विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु सरकारी स्कूलों को गोद लेना इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं।

नोट :

- पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 जून, 2023 से अपने संबंधित ज़िलों में कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत राहगीरी, साइक्लोथॉन, गाँवों में खेल प्रतियोगिताएँ, नशीली दवाओं/नशे के दुरुपयोग के लिये जागरूकता अभियान, वृद्धजनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- इस व्यापक कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम में सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बीच जुड़ाव, भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेगा।
- मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की सभी ज़िलों की प्रस्तुति के साथ छह-मासिक रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और सर्वश्रेष्ठ तीन उपायुक्तों/पुलिस आयुक्तों/पुलिस अधीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएँ होंगी पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को हरियाणा के करनाल ज़िले के 'यातायात एवं हाईवे'के पुलिस महानिरीक्षक हरदीप सिंह दून (आईपीएस) ने बताया कि राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये जो संस्थाएँ अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जएगा।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कॉर्पोरेट हाउस, ऑटो इंडस्ट्रीज एवं उनकी एसोसिएशन, विश्वविद्यालय की संस्थाएँ, गैर सरकारी संगठनों की विभिन्न एजेंसियाँ और ट्रस्ट सोसाईटी आदि को पुरस्कृत किया जाएगा।

नोट :

- इसके लिये इच्छुक संस्था मंत्रालय की वेबसाइट https://morth.nic.in पर पंजीकरण के लिये 30 मई, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
- इस संबंध में इच्छुक संस्थाएँ अपने-अपने प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर भेज सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने की प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में 11 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक की 45 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, ताकि आमजन इन जनकल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
- राज्य सरकार द्वारा फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गाँवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्त्वाकांक्षी रैनीवेल परियोजना पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत आई है।
- बैठक में बताया गया कि ज़िला महेंद्रगढ़ के बालखी में 114 करोड़ रुपए की लागत से पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा।
- इसके अलावा, बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र में 35 गाँवों को नहरी आधारित पेयजल आपूर्ति योजना तथा नूहं में नगीना व पिंगवान ब्लॉक के 52 गाँवों व 5 ढाणियों को जलापूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी तेज गति से चल रहा है, जिसे इस वर्ष के अंत तक पूरा घ्कर लिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि फरीदाबाद से होडल तक जहाँ-जहाँ रैनीवेल आधारित परियोजनाएँ बनाई गई हैं, उस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाए।
- इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिये नहीं किया जाए और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी नज़र रखी जाए।
- पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिये गए हैं कि पानी की चोरी न हो इसके लिये सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही पानी के उचित प्रबंधन हेतू रेगुलेटरी सिस्टम तैयार किया जाए।
- बैठक में बताया गया कि 139 करोड़ रुपए की लागत से पिंजौर में बन रही सेब, फल व सब्जी मंडी का कार्य अंतिम चरण में है। 52 दुकानों में से 39 का आवंटन किया जा चुका है, शेष दुकानों की आवंटन प्रकिया चल रही है। जल्द ही इस मंडी में व्यापार होना शुरू हो जाएगा।
- इसके अलावा, गन्नौर में बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंडी का जून माह में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा।
- बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भिवानी में लगभग 536 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पंडित नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस कॉलेज में दाखिले किये जा सकेंगे।
- इसके अलावा, करनाल के कुटेल में बन रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का काम प्रक्रियाधीन है। इसमें 730 बेड की सुविधा होगी। इस साल के अंत तक यहाँ ओपीडी सेवाओं की शुरुआत करने के लिये विभाग तैयार है।
- साथ ही, प्रदेशभर में बनाए जा रहे 6 नर्सिंग कॉलेज और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज-चरण-2 का कार्य भी तय समयावधि में पूरा हो जाएगा।
- बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। अब विभागों द्वारा डीपीआर बनाने से लेकर अंतिम मंजूरी मिलने तक की सारी प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से होगी।

नोट :

- बैठक में बताया गया कि फरीदाबाद में 325 करोड़ रुपए की लागत से सड़क तंत्र सहित विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है।
- बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेशभर में लंबित चल रही बड़ी परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन हेतु उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की लगातार समीक्षा कर रही है। अब तक 6 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं और इसके परिणामस्वरूप अब तक 1900 करोड़ रुपए की 12 बड़ी परियोजनाएँ पूरी हुई हैं। वर्तमान में 14 विभागों की 90 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

भाला फेंक में नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बने

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी पुरुष भाला फेंक रैंकिंग (javelin throw rankings) में हरियाणा के पानीपत ज़िले के नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बने। नीरज यह रैंकिंग प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं।

प्रमुख बिंदु

- नीरज चोपड़ा इस रैंकिंग में 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 1433 अंकों के साथ विश्व के दूसरे नंबर के भाला फेंक खिलाड़ी हैं।
- टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले चेक गणराज्य के जैकब वडलेज्च 1416 अंकों के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं।
- गौरतलब है कि 5 मई, 2023 को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर भाला फेंककर दोहा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। इसी से वह नंबर वन जेवलिन थ्रोअर बने हैं।
- 30 अगस्त, 2022 को चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुँच गए थे, लेकिन तब से मौजूदा विश्व चैंपियन, एंडरसन पीटर्स उनसे आगे थे।
- सितंबर 2022 में, नीरज ने ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 का फाइनल जीता, जिससे वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए।

नोट :

हरियाणा स्टेट कैम्पा के तहत 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना को दी गई स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में हुई हरियाणा स्टेट कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की 6वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैम्पा) के तहत 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023-24 के दौरान 1,197.73 हेक्टेयर क्षेत्र में कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन, अतिरिक्त कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन और पेनल कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन के लिये 111.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
- विदित है कि राज्य के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिणी भाग में स्थित अरावली पहाड़ी क्षेत्र ढलानदार भू-रचना के कारण भूमि कटाव के लिये बहुत अधिक प्रवर्तनशील और प्रवाहशील हैं।
- राज्य सरकार ने शिवालिक और अरावली पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के बहाव को रोकने के लिये मिट्टी संरक्षण के उपाय किये हैं। इसके लिये 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है।
- इसके अलावा, वन्य प्राणी प्रबंधन योजना 2023-24 के तहत संरक्षित क्षेत्रों में आवास सुधार एवं संरचना विकास के लिये 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य वन्यजीव विंग के माध्यम से 2 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण रिजर्व और 5 सामुदायिक रिजर्व का प्रावधान किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, 20 क्षेत्रीय वन मंडलों में वृक्षों की गणना के लिये 12.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो राज्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने निजामपुर सहित 9 गाँवों में पानी की समस्या दूर करने के लिये 34 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से लगे महेंद्रगढ़ ज़िला के गाँव निजामपुर सहित क्षेत्र के 9 गाँवों में पानी की समस्या को दूर करने के लिये 34 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत 5 और 4 गाँव के दो ग्रुप बनाकर धनचौली माइनर व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से लिंक बनाकर क्षेत्र में पानी के 10 से 12 स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे और पाइप के माध्यम से किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस दौरान गाँव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की मांग को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की और पड़ोस के गाँव नापला में भी कम्युनिटी सेंटर का काम शुरू करवाने की बात भी कही।
- मुख्यमंत्री ने गाँव निज़ामपुर में 16 करोड़ 11 लाख 81 हज़ार रुपए की लागत से बनने वाली तीन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
- इन परियोजनाओं में 346.81 लाख रुपए की लागत से बनने वाले धोलेड़ा बाईपास, गाँव बीघोपुर-धोलेड़ा-ख्वाजपुर के लिये 704 लाख रुपए तथा गाँव इकबालपुर नंगली-नेहरू नगर-भुंगारका के लिये 561 लाख रुपए की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ शामिल हैं।
- धोलेड़ा बाइपास क्षेत्र की पुरानी मांग थी और इस परियोजना के धरातल पर साकार होने से क्षेत्र की सड़कों के ढाँचागत तंत्र में विस्तार होगा। इसी तरह सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को भी इसका लाभ होगा।
- प्रदेश के हर गाँव में पानी पहुँचाने की सोच पर काम करते हुए दक्षिण हरियाणा को यमुना नदी का पानी उपलब्ध कराने के लिये पुराने लिफ्ट सिस्टम को 143 करोड़ रुपए की लागत से नया किया गया है। इस प्रयास से प्रदेश की 300 टेल तक पानी पहुँचा है।

विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई 'विदेश संपर्क कार्यक्रम' की मेजबानी

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और विदेश मंत्रालय के सचिव (कॉन्सुलर, पासपोर्ट एवं वीजा, सीपीवी व प्रवासी भारतीय मामले, ओआईए), डॉ. औसाफ सईद की सह-अध्यक्षता मंर हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के पंचकूला ज़िले में 'विदेश संपर्क कार्यक्रम' की मेजबानी की गई।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय की एक अहम पहल है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करना और उनसे संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकारों के साथ साझेदारी बनाना है।
- विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉन्सुलर और पासपोर्ट सेवाओं, प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने तथा उनके कल्याण और संरक्षण हेतु मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के बारे में हितधारकों और हरियाणा सरकार के अधिकारियों को अवगत करवाया गया।
- इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार व विदेश मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों तथा समस्याओं के समाधान के लिये पारस्परिक सहयोग को और अधिक मज़बूत करने हेतु विचार-मंथन किया गया
- कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों को दूर करने और उनके हितों की रक्षा के लिये स्पेशल 'नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) सेल' गठित करेगी।
- विदित है कि वर्ष 2017 के बाद से तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों के साथ छह आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि विदेश सहयोग विभाग ने हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का गठन किया है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 113 हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सिरसा ज़िले के गाँव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश में हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा को पूरा करते हुए प्रदेशभर में 113 हाई स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप 12वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिये शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
- हरियाणा सरकार द्वारा नियमों में छूट/राहत देते हुए पहले चरण में इन स्कूलों को अपग्रेड करने के उपरांत चरणबद्ध तरीके से अन्य स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा।
- राज्य के 20 ज़िलों के 64 खंडों में कुल 113 हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड होंगे।
- एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेशभर में जिन स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 80 या इससे अधिक है और 1 एकड़ या इससे अधिक भूमि उपलब्ध है तथा सबसे निकटतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल 3 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर है, ऐसे सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
- ज़िला सिरसा के डबवाली एवं सिरसा खंड में 4-4 स्कूल, नाथूसरी चौपटा में 1 स्कूल, रानियाँ तथा ओढ़ा खंड में 2-2 स्कूल अपग्रेड होंगे।
- इसी प्रकार करनाल ज़िले में इंद्री खंड में 2 स्कूल, घरौंडा में 3, नीलोखेड़ी में 2, करनाल में 2, असंध व निसिंग में 1-1 स्कूल तथा ज़िला हिसार में हिसार-।। खंड में 3 स्कूल, उकलाना में 2 स्कूल, बरवाला, अग्रोहा, हांसी, हिसार-1 और आदमपुर खंडों में 1-1 स्कूल अपग्रेड होंगे।
- ज़िला जींद में पिल्लूखेड़ा खंड में 2 स्कूल, नरवाना में 4 स्कूल और सफीदों, जुलाना, जींद व अलेवा खंडों में 1-1 स्कूल को अपग्रेड किया जाना शामिल है।
- पलवल ज़िले में हथीन व हसनपुर खंडों में 2-2 स्कूल और पलवल खंड में 4 स्कूलों तथा ज़िला गुरुग्राम में सोहना खंड में 2 और गुड़गाँव खंड में 6 स्कूल अपग्रेड होंगे। इसी प्रकार ज़िला फतेहाबाद में भूना, रतिया व फतेहाबाद खंडों में 2-2 स्कूलों और जाखल व भट्टू कलाँ में 1-1 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना शामिल है।
- ज़िला कुरुक्षेत्र में पिहोवा व शाहबाद में 3-3 स्कूलों और थानेसर में 1 स्कूल, ज़िला कैथल में कैथल खंड में 3, सिवान, कलायत और पुंडरी में 1-1 स्कूलों तथा ज़िला पंचकूला में पिंजौर व बरवाला खंडों में 2-2 स्कूलों और रायपुररानी में 1 स्कूल अपग्रेड होंगे।
- भिवानी ज़िले में सिवानी व भिवानी खंडों में 2-2 स्कूलों, ज़िला यमुनानगर में साढौरा, बिलासपुर, जगाधरी व छछरौली खंडों में 1-1 स्कूलों, ज़िला अंबाला में अंबाला सिटी में 2 स्कूलों और साहा, नारायणगढ़ व शहजादपुर खंडों में 1-1 स्कूलों, ज़िला सोनीपत गन्नौर में 2 और सोनीपत व मंडलाना में 1-1 स्कूल अपग्रेड होंगे।
- इस सूची में ज़िला फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में 1 स्कूल और फरीदाबाद खंड में 2 स्कूलों, ज़िला रेवाड़ी के रेवाड़ी खंड में 2 स्कूलों, ज़िला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी खंड में 2 स्कूलों, ज़िला रोहतक के रोहतक खंड में 1 स्कूल, ज़िला नूहं के खंड नूंह में 1 स्कूल तथा ज़िला पानीपत के खंड समालखा में 1 स्कूल को अपग्रेड किया जाना शामिल है।
- प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने व गुणवत्तापरक बनाने के लिये राज्य में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पी.एम. श्री) स्कूल स्थापित किए जाएंगे। पीएम श्री स्कूलों के विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- पीएम श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के रूप में की गई है। प्रदेश में हर ब्लॉक में दो स्कूल, (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय) खोले जाएंगे और उन्हें पी.एम. श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

नोट :

सलेमपुर में 5 करोड़ की लागत से वीटा चिलिंग प्लांट प्रथम फेज का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2023 को हरियाणा के कृषि मंत्री जे.पी. दलाल ने प्रदेश के भिवानी ज़िले के सलेमपुर गाँव में करीब पाँच करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वीटा चिलिंग प्लांट के प्रथम फेज का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस चिलिंग प्लांट से लोहारू के अलावा तोशाम, बाढड़ा व सतनाली के पशुपालकों को सीधा लाभ होगा। चिलिंग प्लांट बनने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- कृषि मंत्री ने कहा कि वीटा अपने आप में एक नाम है और यहाँ बनने वाले वीटा प्रोडेक्ट्स को गुजरात की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
- प्रथम फेज में इसकी क्षमता 20 हजार लीटर प्रतिदिन की होगी, जबकि दूसरे और तीसरे साल में इसकी क्षमता को 40 हजार लीटर तक बढ़ाया जाएगा।
- विदित है कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ सर्वाधिक पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपए की राशि के पशु क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर चार प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण सहायता मुहैया करवाई जा रही है।
- कृषि मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे अच्छी नस्ल के पशु के लिये कृत्रिम गर्भाधान करवाएँ। नस्ल सुधार से दूध का उत्पादन बढ़ेगा।
- हरियाणा प्रदेश पूरे देश में दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर आ गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि दूध उत्पादन में प्रदेश का देशभर में पहला स्थान हो। इसलिये राज्य सरकार नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पशुपालन को बढ़ावा दे रही है।

नोट :

हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में फिजियोथेरेपिस्टो को काम करने के लिये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने की तरफ एक और महत्त्वपूर्ण कदम है और फिजियोथेरेपिस्टों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने से समय के साथ-साथ रुपए की बचत, डिजिटल ऑटोमेशन, एनहांस एफीसिएंसी, केंद्रीकृत डेटाबेस, त्रुटिमुक्त कार्यक्षमता, संचार में सुधार करने, पेपर वर्क कम करने और पारदर्शिता लाने में लाभ मिलेगा।
- विदित है कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे राज्य की काउंसिल में पंजीकृत है और प्रदेश में काम करने के इच्छुक है, तो उसे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये उस काउंसिल की एनओसी जमा करवानी होगी। यदि उस राज्य में काउंसिल नहीं है तो उसकी डिग्री की वेरिफीकेशन करवाई जाएगी।
- इस पोर्टल से नए रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर जाँच सूची, राशि भुगतान, रसीद व पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने तक ऑनलाइन रहेगी।
- गौरतलब है कि राज्य स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी में अब तक 1936 रजिस्ट्रेशन मैन्युअल है।
- काउंसिल पर फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होने पर जब उसे प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा तो उसकी पूरी सूची काउंसिल की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ साइन किया एमओयू

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने राज्य में छात्र-छात्राओं को उत्तम गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिये गुरुग्राम ज़िले के पाथवेज स्कूल में शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर की उपस्थिति में जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) के इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के शिक्षा स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिये राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं आईबी बोर्ड के साथ एमओयू किया गया है।
- इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आईबी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे अध्यापन के स्तर में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वीकार्यता होगी। इस दिशा में जल्द ही प्रदेश के विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
- ज्ञातव्य है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव के बेहतर शैक्षणिक, सुधारात्मक व सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ही बोर्ड नई ऊँचाइयां छू रहा है। बहुत कम समय के कार्यकाल में उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, प्रथम बार पाठ्य योजना व चरणबद्ध मूल्यांकन योजना तैयार करवाने जैसी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

नोट :